पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कार्य-निष्पादन समीक्षा - दिनांक 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही

पीएफसी ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को दिनांक 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणाम की उद्घोषणा की। तिमाही1'22 के लिए कार्य-निष्पादन विशेषताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क) वित्तीय कार्य-निष्पादन – तिमाही1'22

1) समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन

- तिमाही1'21 से कर पश्चात समेकित लाभ में 28% की वृद्धि - तिमाही'22 के लिए 4,555 करोड़ रुपए पर कर पश्चात लाभ
- तिमाही1'21 से परिचालनों से समेकित राजस्व में 12% की वृद्धि - तिमाही'22 के लिए 18,965 करोड़ रुपए पर समेकित राजस्व
- दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के कारण तिमाही1'21 में 3.15% से तिमाही1'22 में 1.80% की समेकित निवल एनपीए अनुपात में कमी।
- समेकित ऋण परिसंपत्ति बुक 9.5% तक बढ़ा - दिनांक 30.06.2021 तक 7,49,373 करोड़ रुपए बनाम दिनांक 30.06.2020 तक 6,84,383 करोड़ रुपए

2) एकल वित्तीय कार्य-निष्पादन

- तिमाही1'21 से कर पश्चात एकल लाभ में 34% की वृद्धि - तिमाही'22 के लिए 2,274 करोड़ रुपए पर कर पश्चात लाभ
- प्रति शेयर घोषित 2.25 रुपए का अंतरिम लाभांश
- पीएफसी पर्याप्त पूंजी बफर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तदनुसार, पीएफसी ने 20% से अधिक का सीआरएआर स्तर प्राप्त किया है - सीआरएआर में तिमाही1'21 से 384 बीपीएस की वृद्धि हुई है। दिनांक 30.06.2021 को सीआरएआर 21.16% है जिसमें 17.56% की टीयर I पूंजी और 3.60% की टीयर II पूंजी है। इसके अतिरिक्त, पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में होगा। अतः यह उपलब्ध पूंजी बफर को नीचे लाएगा और परिणामस्वरूप आगे बढ़ने वाले सीआरएआर के स्तर पर असर पड़ेगा।

- **प्रमुख वित्तीय संकेतक**
  - तिमाही1'22 के लिए अर्जक परिसंपत्तियों पर प्रतिफल 10.39% के अनुमानित स्तरों के भीतर है। पिछले वर्ष पीएफसी ऋणकर्ताओं को दी गई ब्याज दर में कटौती का असर अब हमारे प्रतिफल पर दिखना शुरू हो गया है, जिससे प्रतिफल घट रहा है।
  - तिमाही1'22 के लिए निधियों की लागत 7.43% पर है - तिमाही1'21 से 25 बीपीएस की कमी दर्ज की गई। यह बाजार की स्थितियों के अनुरूप है।
  - निधियों की लागत में कमी से प्रतिफल में गिरावट को मामूली रूप से ऑफसेट किया गया है, जिससे तिमाही1'22 के लिए स्प्रैड 2.96% तक पहुंच गया है।

- तिमाही1'22 के लिए अर्जक परिसंपत्तियों पर एनआईएम 3.70% है- तिमाही1'21 से 22 बीपीएस की वृद्धि। पिछले वर्ष विभिन्न दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के सकारात्मक प्रभाव से एनआईएम स्तरों में सुधार हुआ है।

- ऋण परिसंपत्ति बुक - दिनांक 30.06.2021 तक 3,69,983 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्ति बुक। पिछली प्रवृत्ति के अनुरूप, इस वर्ष की पहली तिमाही में संवितरण धीमा रहा है। अतः इससे तिमाही1'22 में कमजोर ऋण परिसंपत्ति वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्ष की दूसरी छमाही में संवितरण गति पकड़ेगा, आगे चलकर ऋण परिसंपत्ति वृद्धि पिछले वर्ष के समान स्तर पर रहने की परिकल्पना की गई है।

चुनौतीपूर्ण परिचालनगत वातावरण में तिमाही1'22 के लिए स्वस्थ वित्तीय कार्य-निष्पादन किया।

ख) परिसंपत्ति गुणवत्ता

1) एनपीए स्तरों में सुधार

- संवर्धित प्रावधान स्तरों के कारण, दिनांक 30.06.2021 को निवल एनपीए अनुपात घटकर 2.00% हो गया, जो पिछले 3 वर्ष में सबसे कम है। दिनांक 30.06.2021 को सकल एनपीए अनुपात 5.72% है।
- वर्तमान में, चरण III की कुल परिसंपत्ति (एनपीए परिसंपत्ति) 21,154 करोड़ रुपए है।

2) समाधान स्थिति का अद्यतन

- वर्तमान में, 21,154 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाएं चरण III में हैं। इनमें से 15,820 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का एनसीएलटी के माध्यम से समाधान किया जा रहा है और 5,334 करोड़ रुपए की बाकी 10 परियोजनाओं का एनसीएलटी से बाहर समाधान किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, 2,109 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं अर्थात 1200 मेगावाट एस्सार पावर महान का 1,345 करोड़ रुपए का ऋण और 600 मेगावाट झाबुआ पावर का 764 करोड़ रुपए का ऋण, समाधान के अग्रिम चरण में हैं। इन दोनों परियोजनाओं में समाधान योजना एनसीएलटी में दायर की गई हैं। इन परिसंपत्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है।

3) प्रावधान की स्थिति

- चरण I की परिसंपत्ति में, डिस्कॉम(मों) की रेटिंग में संशोधन के कारण मुख्य रूप से लगभग 219 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रावधान पीएफसी के ईसीएल मॉडल पर आधारित है, जिसमें अन्य कारकों के साथ, ऋणकर्ता की रेटिंग पर भी विचार किया जाता है। डिस्कॉम के लिए, पीएफसी रेटिंग वितरण कंपनियों के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अधिसूचित एकीकृत रेटिंग के समान है। आईसीआरए एवं केयर ऐसी रेटिंग के लिए नामित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग कार्य का समन्वय करने का कार्य पीएफसी को सौंपा गया है। हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉम(मों) के लिए एक संशोधित रेटिंग जारी की है। तदनुसार, इसका प्रभाव हमारे ईसीएल मॉडल में आ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उच्च प्रावधान स्तर प्राप्त हुआ है।

- चरण III की परिसंपत्तियों में, एक लचीला तुलन-पत्र बनाने पर ध्यान देने के साथ, प्रावधान कवरेज को तिमाही4'21 में 63% से तिमाही1'22 में 65% तक बढ़ाया गया है।

लक्षित समाधान दृष्टिकोण और पर्याप्त प्रावधान स्तरों से भविष्य में निवल एनपीए स्तरों में सुधार की आशा है

ग) भारत सरकार की आत्म निर्भर डिस्कॉम योजना

1) भारत सरकार की आत्म-निर्भर डिस्कॉम योजना की स्थिति

- भारत सरकार की आत्म-निर्भर डिस्कॉम योजना के अंतर्गत, अब तक पीएफसी ने 67,699 करोड़ रुपए संस्वीकृत और 38,501 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। पीएफसी और उसकी सहायक कंपनी आरईसी के लिए संयुक्त रूप से 1,35,537 करोड़ रुपए की संस्वीकृती और 79,678 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया है।

- हम आशा कर रहे हैं कि संवितरण धीरे-धीरे बढ़ेगा क्योंकि ट्रांच II संवितरण पाइपलाइन में है।

2) रीवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम: एक सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध योजना

- भारत सरकार ने दिनांक 30.06.2021 को एक सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध, रीवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम शुरू की।
- योजना द्वारा आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु डिस्कॉम(मों) को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र के डिस्कॉम(मों) को छोड़कर सभी डिस्कॉम(मों)/विद्युत विभागों की परिचालनगत क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने की मंशा है।
- यह योजना सरकार के पूर्ववर्ती वितरण सुधार उपायों से हटकर है, चूंकि सरकार से वित्तीय सहायता सुधारों को जारी रखने और परिणामों की उपलब्धि पर ही निर्भर होता है।
- योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु पीएफसी और आरईसी को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।
- इस योजना में 3,03,758 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, जिसमें केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपए की अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) होगी। आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई की योजनाओं के साथ जम्मू एवं कश्मीर (जे एवं के) और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत वर्तमान में चल रही अनुमोदित परियोजनाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- **<u>योजना के उद्देश्य:</u>**
  - वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना।
  - 2024-25 तक एटी एवं सी हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।
  - 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना।
- **<u>प्रमुख घटक:</u>**
  - उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग
  - वितरण अवसंरचनात्मक कार्य
  - प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य समर्थक एवं सहायक गतिविधियां
- यह योजना वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी। यह योजना निजी डिस्कॉम को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

सरकार की रीवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आगे चलकर पीएफसी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है।

घ) ऋण

- विविधीकरण के हमारे उद्देश्य के अनुरूप, पीएफसी ने पहली बार 3 माह की टी-बिल दर से जुड़े फ्लोटिंग दर बॉण्ड संरचना के माध्यम से निधियन के अवसर ढूंढे और 3 वर्ष की अवधि के लिए सफलतापूर्वक 1,985 करोड़ रुपए जुटाए। यह बाजार के प्लेयरों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है।

- विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर, पीएफसी 5 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ पोर्टफोलियो के लिए विनिमय जोखिम पर 86 प्रतिशत हैज अनुपात बनाए रखे हुए है।

पीएफसी की उच्च क्रेडिट योग्यता, सुस्थापित संबंधों और विविधीकरण पर सुसमर्पित ध्यानकेंद्रण के साथ, हमें आशा है कि पीएफसी अपनी संवर्धक गतिविधि में लागत दक्षता प्राप्त करता रहेगा।

ड़) भावी आउटलुक

पूर्व में संरेखित लक्ष्यों के अनुरूप:

- पीएफसी का ध्यान टी एंड डी और नवीकरणीय बिजनेस तथा डिस्कॉम क्रेडिट पैकेज के अंतर्गत ऋण देने पर रहेगा।
- ऋण परिसंपत्ति वृद्धि पिछले वर्ष की तरह समान स्तर पर रहने की संभावना है।
- पीएफसी रीवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और पुनर्वित्तपोषण बिजनेस में व्यावसायिक अवसर की परिकल्पना कर रहा है।

***